भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों को मजबूती

भारत-उज्बेकिस्तान के बीच बढ़ेगा आर्थिक और रणनीतिक सहयोग

एक अरब डॉलर के व्यापार को और विस्तार देने पर जोर

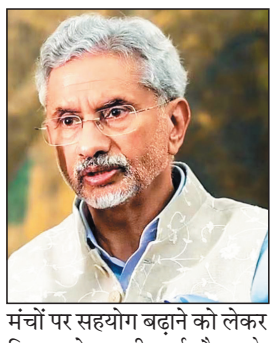

> सबसे अहम घोषणा के रूप में भारत ने वर्ष 2027 से 2029 तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) की अध्यक्षता के लिए उज्बेकिस्तान को समर्थन देने का भरोसा दिया. जयशंकर ने कहा कि भारत उज्बेकिस्तान की इस भूमिका का समर्थन करेगा. इससे दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है.

नई दिल्ली, 04 अगस्त भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा सहयोग के नए क्षेत्रों में विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की है.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडिलोविच और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की. इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने को लेकर विस्तार से बातचीत हुई. बैठक के बाद जयशंकर ने कहा कि भारत उज्बेकिस्तान को अपने विस्तारित पड़ोस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है. दोनों देशों के बीच संबंध केवल राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनसंपर्क की मजबूत नींव पर आधारित हैं.

उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लोगों, विचारों और व्यापार का लगातार आदान-प्रदान होता रहा है, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा दी है. विदेश मंत्री ने कहा कि आधुनिक दौर में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच राजनीतिक और संस्थागत संपर्क लगातार मजबूत हो रहे हैं. दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच नियमित संवाद बना हुआ है. उन्होंने विश्वास जताया कि यह बैठक भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों को और गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग का दायरा काफी विस्तृत हुआ है.

निर्माण क्षेत्र से लेकर ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य और शिक्षा तक कई क्षेत्रों में साझेदारी आगे बढ़ रही है. भारत अब इस सहयोग को खनन जैसे नए क्षेत्रों तक ले जाने की दिशा में भी काम करना चाहता है. उन्होंने बताया कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच वर्तमान में करीब एक अरब डॉलर का व्यापार हो रहा है.

इमामी मुनाफा 15% घटकर 139 करोड़

कोलकाता, 04 अगस्त सौंदर्य प्रसाधन एवं स्वास्थ्य उत्पाद बनाने वाली एफएमसीजी कंपनी इमामी को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में समेकित आधार पर 139 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 15 प्रतिशत की गिरावट है. कंपनी के निदेशकमंडल की मंगलवार को हुई बैठक के बाद वित्तीय परिणामों की घोषणा की गयी. इस दौरान परिचालन से कंपनी का राजस्व 15 प्रतिशत बढ़कर 1,039 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. हालांकि कच्चे माल की लागत में 29 प्रतिशत की भारी भरकम बढ़ोतरी के कारण उसका मुनाफा कम हुआ है. कंपनी ने बताया कि उसका परिचालन लाभ छह प्रतिशत बढ़कर 226 करोड़ रुपये और कर पूर्व लाभ चार प्रतिशत बढ़कर 196 करोड़ रुपये हो गया.

लोकसभा में आज पेश होगा कराधान संशोधन बिल

2026, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रखेंगी प्रस्ताव

आयकर अध्यादेश जारी करने के कारणों पर देंगी स्पष्टीकरण

नई दिल्ली, 04 अगस्त संसद के मानसून सत्र में मंगलवार का दिन वित्तीय और विधायी कामकाज के लिहाज से अहम रहने वाला है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करेंगी.

सदन की संशोधित कार्य सूची में इस महत्वपूर्ण विधेयक को शामिल किया गया है. इस बिल के जरिए भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, आयकर अधिनियम, 2025 और वित्त अधिनियम, 2026 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है.

वित्त मंत्री सदन में विधेयक पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव रखेंगी और इसके बाद इसे लोकसभा में प्रस्तुत करेंगी. इसके साथ ही वे आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 जारी किए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला व्याख्यात्मक बयान भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सदन के पटल पर रखेंगी. केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से संबंधित समिति की सिफारिशों पर जानकारी देंगे. वहीं राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी भूमि संसाधन विभाग और राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी सिफारिशों के पालन पर बयान रखेंगे. लोकसभा में आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक, 2026 पर भी चर्चा होगी.

> लोकसभा की कार्यवाही में आज कई अन्य वित्तीय विषय भी शामिल हैं. सदन वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगा. चर्चा पूरी होने के बाद वित्त मंत्री विनियोग (नंबर-3) विधेयक, 2026 पेश करेंगी. इस विधेयक के माध्यम से उस अतिरिक्त खर्च के लिए संसद की मंजूरी मांगी जाएगी, जो 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत राशि से अधिक हुआ था. इसके अलावा संसद में विभिन्न स्थायी समितियों की सिफारिशों के क्रियान्वयन से जुड़े मंत्रियों के बयान भी प्रस्तुत किए जाएंगे.

डाबर के कई उत्पादों की बिक्री पर रोक

100 प्रतिशत शुद्ध' और '100 प्रतिशत प्राकृतिक' दावों पर आपत्ति

कार्रवाई के बाद शेयर 2.85 प्रतिशत गिरकर 413.65 रुपये पर

नई दिल्ली, 04 अगस्त भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया के कई खाद्य उत्पादों पर किए गए कथित भ्रामक दावों को लेकर सख्त कार्रवाई की है.

खाद्य नियामक ने कंपनी को ऐसे उत्पादों की बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया है, जिन पर '100 प्रतिशत प्राकृतिक', '100 प्रतिशत शुद्ध', '100 प्रतिशत शुद्धता की गारंटी' और '100 प्रतिशत कोमल नारियल पानी' जैसे दावे किए गए हैं. नियामक की कार्रवाई की खबर सामने आने के बाद डाबर इंडिया के शेयर में भी दबाव देखने को मिला और कारोबार के दौरान शेयर करीब 3 प्रतिशत तक गिर गया.

खाद्य सुरक्षा नियामक के अनुसार, इन दावों को अस्पष्ट और पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं माना गया है. ऐसे दावों से उपभोक्ताओं के गुमराह होने की आशंका जताई गई है. नियामक ने कहा कि इस तरह के दावे खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं.

नियामक ने डाबर के कुछ जैविक उत्पादों की पैकेजिंग को लेकर भी आपत्ति जताई है. डाबर हिमालयन जैविक सेब का सिरका और डाबर जैविक शहद पर वैध जैविक मंजूरी के बिना 'जैविक भारत' चिह्न का इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई है.

> हालांकि, नियामक के अनुसार कंपनी की ओर से इस संबंध में संतोषजनक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद अब पहचाने गए उत्पादों की बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया है .कंपनी को नियामक ने 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने को कहा है. इस रिपोर्ट में बिक्री रोकने और नियामकीय निर्देशों के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी.

नवी मुंबई से अंतरराष्ट्रीय माल उड़ान शुरू

नवी मुंबई, 04 अगस्त नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय मालवाहक उड़ान का परिचालन भी शुरू हो गया है. इस हवाई अड्डे से पहली समर्पित अंतरराष्ट्रीय मालवाहक उड़ान गत 02 अगस्त को शारजाह के लिए रवाना हुई.

हवाई अड्डे की संचालक कंपनी अडानी एयरपोर्ट्स ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में इंडिगो कार्गो द्वारा संचालित इस पहली मालवाहक उड़ान को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि करार देते हुए कहा कि इससे मुंबई महानगर क्षेत्र और पश्चिमी भारत के लिए एक नये एयर कार्गो गेटवे के रूप में हवाई अड्डे की भूमिका और मजबूत हुई है.

इस उड़ान में लगभग 20 टन कार्गो भेजा गया, जिसमें सामान्य माल और जल्द खराब होने वाली वस्तुएं शामिल थीं. इस खेप में मुंबई और अहमदाबाद से प्राप्त बॉन्डेड ट्रांसफर कार्गो भी शामिल था, जिसे बॉन्डेड ट्रकिंग व्यवस्था के माध्यम से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया था.

यह संचालन नवी मुंबई हवाई अड्डे के एकीकृत कार्गो इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

जीआई टैग से मिलेगी भारत को वैश्विक पहचान

कारीगरों और किसानों की आय बढ़ाने में मिलेगी मदद

नई दिल्ली, 04 अगस्त भारत की समृद्ध पारंपरिक कला, संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को देश-दुनिया में नई पहचान दिलाने में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. यह टैग किसी उत्पाद को उसके विशेष भौगोलिक क्षेत्र और पारंपरिक उत्पादन पद्धति से जोड़ता है.

इससे उत्पाद की असली पहचान और गुणवत्ता सुरक्षित रहती है तथा नकली उत्पादों पर रोक लगाने में मदद मिलती है. साथ ही स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिलने की संभावना बढ़ती है. केंद्र सरकार के अनुसार, जीआई टैग भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी प्रभावी माध्यम बन रहा है. बनारसी साड़ी इसका प्रमुख उदाहरण है. जीआई टैग मिलने के बाद बनारसी साड़ी की पारंपरिक पहचान सुरक्षित हुई है और इससे जुड़े बुनकरों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिली है. वस्त्र मंत्रालय के अनुसार, जीआई टैग वाले उत्पादों से ग्रामीण कारीगरों की आय में 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है.

> देश-विदेश में आयोजित व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भी जीआई उत्पादों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जा रहा है. सरकार ने वर्ष 2030 तक देश में 10 हजार जीआई पंजीकरण का लक्ष्य रखा है. इस पहल के जरिए भारत की पारंपरिक कला, शिल्प, कृषि और खाद्य उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिलाने के साथ उन क्षेत्रों से जुड़े कारीगरों और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है.

इससे पारंपरिक शिल्प को संरक्षण मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं. सरकार के मुताबिक, भारत में अब तक 800 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है.

बाढ़ पीड़ितों के लिए रिलायंस देगा 21 करोड़

गुवाहाटी, 04 अगस्त रिलायंस फाउंडेशन ने असम में बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है.

यह राशि फाउंडेशन की ओर से राज्य में पहले से चलाए जा रहे राहत कार्यों के अतिरिक्त दी जाएगी. फाउंडेशन के कर्मचारी पहले से ही शिवसागर और चराइदेव जिलों में भोजन, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्थायी आश्रय और पशुओं की देखभाल से जुड़े कार्यों में हुए हैं.

फाउंडेशन की संस्थापक एवं अध्यक्ष नीता एम. अंबानी ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा, 'आप अकेले नहीं हैं. हम आपके साथ खड़े हैं और आने वाले दिनों में भी आपके साथ बने रहेंगे.

शेयर बाजारों की तेजी पर लगा ब्रेक

210 अंक पर टूटा सेंसेक्स

159 अंक से नीचे आया निफ्टी

नयी दिल्ली, 04 अगस्त अमेरिका-ईरान शांति वार्ता को लेकर बनी अनिश्चितता और कच्चे तेल में तेजी से घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को शुरुआती तेजी के बाद गिरावट देखी गयी.

बीएसई का सेंसेक्स सुबह 500 अंक से ज्यादा चढ़ने के बाद दोपहर से पहले ही लाल निशान में उतर गया. अंत में 210.08 अंक (0.27 प्रतिशत) की गिरावट में 78,428.95 अंक पर बंद हुआ.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 159.40 अंक यानी 0.64 प्रतिशत टूटकर 24,614.90 अंक पर बंद हुआ. पिछले कारोबारी दिवस पर यह पांच महीने के उच्चतम स्तर पर रहा था. ईरान ने अमेरिका के इस दावे का खंडन किया है कि दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत हो रही है. इसके बाद, घरेलू शेयर बाजार में निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से भी भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट रही.

> वृहत बाजार में भी बिकवाली ज्यादा देखी गयी. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.47 प्रतिशत नीचे बंद हुआ. वहीं, छोटी कंपनियों में लिवाली से निफ्टी स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.23 प्रतिशत मजबूत हुआ .निफ्टी धातु और मीडिया को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों के सूचकांक लाल निशान में बंद हुए.

पीएफ की वेतन सीमा 15 से बढ़कर 25 हजार होगी

नई दिल्ली, 04 अगस्त नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कर्मचारी भविष्य निधि के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा को मौजूदा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद 15 हजार से 25 हजार रुपये के बीच मूल वेतन पाने वाले बड़ी संख्या में कर्मचारी अनिवार्य भविष्य निधि और पेंशन योजना के दायरे में आ सकते हैं.

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का मुनाफा 3% बढ़ा

नई दिल्ली, 04 अगस्त एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्रदर्शन बेहतर रहा. कंपनी ने बताया कि जून 2026 को समाप्त तिमाही में उसका एकल शुद्ध लाभ सालाना आधार पर तीन प्रतिशत बढ़कर 873 करोड़ रुपये हो गया.

पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 845 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था. कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही के दौरान उसकी कुल आय पांच प्रतिशत बढ़कर 1,385 करोड़ रुपये हो गई. एक साल पहले की समान अवधि में कुल आय 1,324.8 करोड़ रुपये रही थी. हालांकि, इस दौरान कंपनी के कुल खर्च में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई.

टिकट नहीं, बगावत तय करेगी चुनाव!

भाजपा, सपा- बसपा और कांग्रेस किस पार्टी में हो होगा सिर फुटव्वल?

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव सिर्फ जनता के बीच नहीं लड़ा जाता, बल्कि उसकी एक बड़ी लड़ाई राजनीतिक दलों के भीतर भी होती है. जैसे-जैसे चुनाव करीब आता है. टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ने लगती है.

कोई अपने पांच साल का काम गिनाता है. तो कोई संगठन में अपनी पकड़ दिखाता है. जब इन सबसे बात नहीं बनती तो कोई जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी हवाला देने में पीछे नहीं रहता. लेकिन टिकट तो किसी एक को ही मिलता है. यहीं से शुरू होती है नाराजगी, गुटबाजी और कई बार खुली बगावत. उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन हर सीट पर टिकट मांगने वालों की संख्या कई बार दर्जनों में पहुंच जाती है. जिसके बाद बगावत की आग उठती है. यही वजह है कि टिकट वितरण किसी भी पार्टी के लिए सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा माना जाता है.

बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?- सबसे पहले बीजेपी की ही बात करते हैं. लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरेगी. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होगा कि कितने मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका मिलेगा और कितने नए चेहरों पर दांव लगाया जाएगा. अगर बड़ी संख्या में टिकट बदले जाते हैं, तो कुछ क्षेत्रों में नाराजगी बढ़ सकती है. वहीं अगर अधिकांश पुराने चेहरों को दोहराया जाता है, तो एंटी-इनकंबेंसी का सवाल भी उठ सकता है. भाजपा के सामने संगठन और सरकार दोनों के बीच संतुलन बनाना भी अहम चुनौती होगी.

समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा दावेदार? 2024 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है. यही वजह है कि 2027 के टिकट के लिए पार्टी में दावेदारों की संख्या पहले से ज्यादा रहने की संभावना है.

सबसे बड़ा सवाल- कौन संभालेगा अपनी पार्टी?

2027 के चुनाव में भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस चारों दलों के सामने सिर्फ विपक्ष को हराने की चुनौती नहीं होगी. उन्हें अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी साथ लेकर चलना होगा. जो पार्टी टिकट बांटने में सामाजिक संतुलन, स्थानीय समीकरण, संगठन और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं के बीच बेहतर तालमेल बना पाएगी, उसकी चुनावी स्थिति मजबूत हो सकती है. यूपी की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि चुनाव का आधा संघर्ष टिकट तय होने से पहले ही शुरू हो जाता है. इसलिए 2027 की लड़ाई में टिकट बंटवारा भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा, जितना चुनाव प्रचार.

शिक्षा पर बहस से बाहर रहे थरूर, तिवारी

नई दिल्ली. कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा के अनुशासन और एक नेता के प्रति सबके समर्पण को लेकर भाजपा और संघ का मजाक उड़ाते हैं. लेकिन असल में कांग्रेस में भी सब कुछ वैसा ही है, जैसा भाजपा में है.

कांग्रेस में भी आलाकमान के खिलाफ बोलने या उससे अलग राय रखने वालों के लिए कोई जगह नहीं है. उनको भी किनारे कर दिया जाता है. लोकसभा में पेपर लीक बिल पर हुई चर्चा में जिस तरह से कांग्रेस के कुछ अच्छे वक्ताओं और शिक्षा पर लिखने, बोलने वालों को चर्चा से दूर रखा गया उससे भी यह साबित हुआ है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर और मनीष तिवारी दोनों को चर्चा में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला. शशि थरूर न सिर्फ अच्छे वक्ता हैं, बल्कि वे लगातार शिक्षा और परीक्षा की व्यवस्था पर लिखते रहे हैं. उन्होंने आंदोलन के दौरान इस विषय पर बहुत अच्छे लेख लिखे. इसी तरह मनीष तिवारी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव दिया था और इस पर चर्चा की मांग की थी. लेकिन इन दोनों को वक्ताओं में शामिल नहीं किया गया. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बोलें तो समझ में आता है. लेकिन हर बार वही गौरव गोगोई, वही दीपेंद्र हुड्डा और वही केसी वेणुगोपाल बोलते हैं. असल में मनीष तिवारी ने पिछले दिनों कई ऐसे बयान दिए, जो कांग्रेस आलाकमान को पसंद नहीं आए होंगे. ऊपर से चंडीगढ़ में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर मौजूद थे.

वारिस पंजाब दे से बढ़ी शिअद की चुनौती

पंथक वोट बैंक में आएगा बिखराव

जालंधर. पंजाब की राजनीति में पंथक मुद्दे एक बार फिर केंद्र में आ गए हैं. लंबे समय तक सिख राजनीति की सबसे प्रभावशाली ताकत रहे शिरोमणि अकाली दल (बादल) के सामने अब चुनौती केवल आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा से नहीं बल्कि उभर रहे अकाली दल वारिस पंजाब दे से भी है. हाल के घटनाक्रम संकेत दे रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंथक राजनीति का केंद्र तेजी से बदल रहा है.

पंथक राजनीति हमेशा सिख धार्मिक पहचान, बंदी सिखों की रिहाई, बेअदबी के मामलों, श्री अकाल तख्त साहिब और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसे मुद्दों के इर्द-गिर्द रही है. लंबे समय तक शिअद बादल इसका सबसे बड़ा प्रतिनिधि रहा लेकिन पिछले एक दशक में उसकी पंथक विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठे हैं. बेअदबी की घटनाओं, शासनकाल के विवादित फैसलों और सुखबीर सिंह बादल को श्री अकाल तख्त की ओर से तनखैया घोषित किए जाने के घटनाक्रम ने पार्टी की साख को प्रभावित किया. इसी माहौल में सांसद अमृतपाल सिंह के नेतृत्व से जुड़ा अकाली दल वारिस पंजाब दे संगठन का तेजी से विस्तार कर रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों और सिख युवाओं में इसकी सक्रियता बढ़ी है. बंदी सिखों की रिहाई और धार्मिक मुद्दों पर आक्रामक रुख ने इसे नई पहचान दिलाई है.

हाल ही में चंडीगढ़ में अमृतपाल सिंह समेत अन्य बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन ने पंथक राजनीति को फिर चर्चा में ला दिया.

विशेष पंजाब में अगले साल होने है विधानसभा चुनाव, सिंह सिद्धू कहां हैं?

नवजोत सिंह सिद्धू क्या राजनीति में लौटेंगे

चंडीगढ़. पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले कुछ समय से राजनीति से दूरी बनाई हुई है. पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू क्या राजनीति में लौटेंगे. हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने इसे लेकर अबतक कोई संकेत नहीं दिया है. पिछले चुनावों में एक्टिव रहने वाले सिद्धू इन दिनों इन दिनों वो पंजाब में भी नहीं है. सिद्धू इन समय कहां और क्या कर रहे इसे लेकर भी लोगों के मन में सवाल है. बता दें कि सिद्धू इन दिनों धार्मिक यात्रा पर निकले हुए है.

मई महीने में जब नवजोत सिंह सिद्धू वृंदावन पहुंचे थे तो उन्होंने खुद बताया था कि वो धार्मिक यात्रा पर है. इस दौरान उन्होंने राजनीतिक सवालों का कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया था. वहीं पिछले दिनों वो उत्तराखंड पहुंचे. वो इस साल लगातार दूसरी बार मां सुरकंडा देवी मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने तीन दिन तक मंदिर में पूजा-अर्चना की और घंटों ध्यान-साधना भी की. सिद्धू को मां सुरकंडा मंदिर इतना भाया कि वे इसी वर्ष दूसरी बार मंदिर पहुंचे और मंदिर में पूरे तीन दिन तक पूजा-अर्चना की. शांति और सुकून के लिए उन्होंने मंदिर में घंटों ध्यान-साधना भी की.

नवजोत सिंह सिद्धू ने लंबे समय से राजनीति से दूरी बनाई हुई. उन्होंने एक बार फिर से टीवी और कमेंट्री में वापसी कर ली है. वहीं उनकी पत्नी नवजोत कौर ने अपनी नई पार्टी बनाने के संकेत दिए है.

ऐसे में अगर नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति में वापसी करते हैं तो वो कांग्रेस या बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे. अगर उनकी पत्नी पार्टी बनाती है तो हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी दोनों चुनाव लड़ें. हालांकि इसे लेकर अभी दोनों की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है.

बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए थे सिद्धू

बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने साल 2004 में बीजेपी में शामिल ज्वाइन की थी. वो अमृतसर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे थे. लेकिन, 15 जनवरी, 2017 को उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था. कांग्रेस में आने के बाद वह अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीते थे. जुलाई 2021 में कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया. नवजोत सिंह सिद्धू 2022 में आम आदमी पार्टी की जीवन ज्योत कौर के सामने हार गए थे.